क्रांति समय
हिन्दी दैनिक अखबार में विज्ञापन, प्रैस नोट, जन्म दिन की शुभकामनाएँ, या अपने विस्तार में किसी भी समस्या को अखबार में प्रकाशित करने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 9879141480

दैनिक
# क्रांति समय

RNI.No. : GUJHIN/2018/75100

क्रांति समय
हमारे यहां पर एल.आई.सी., कार-बाईक-ट्रक का इन्सयोरेंशन, रेल टिकट, एयर टिकट बनवाने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 8980974047

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480
E-mail: krantisamay@gmail.com
सूरत, वर्ष: 02 अंक: 10, शनिवार, 02 फरवरी, 2019, पेज: 4, मुल्य 1 रु.
रजीस्ट्रड ऑफिस:- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात
Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

## वित्त मंत्री के पिटारे से आपको क्या मिला

## बजट की 25 मुख्य बातें

नई दिल्ली । लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार की ओर से पेश किए अंतरिम बजट में देश के हर वर्ग के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गईं। अरुण जेटली की जगह बजट पेश कर रहे पीयूष गोयल ने आने वाले वर्षो में देश के विकास क साथ आम जनता को राहत देने वाली योजनाओं का खाका खींचा। साथ ही, भारत को विश्व का एक अग्रणी देश बनाने के लिए काम करने की प्रतिबद्धता भी जताई। आइए जानते हैं कुछ उन मुख्य घोषणाओं को, जो आने वाले समय में आपकी जिंदगी को प्रभावित करने वाली हैं।

- इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव। अब पांच लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे लगभग तीन करोड़ करदाताओं को फायदा होगा।
- स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये किया।
- ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए की गई।
- यदि 6.5 लाख रुपये तक की कमाई करने वाले प्रोविडेंट फंड और अन्य इक्विटीज में निवेश करते हैं तो कोई टैक्स नहीं देना होगा।
- बोनस की सीमा बढ़ाई, अब 21 हजार रुपये मासिक आय तक वालों को मिलेगा बोनस
- 2 हेक्टेयर तक जमीन वाले किसानों के खाते में हर साल 6 हजार रुपये, 12 करोड़ किसान परिवारों को मिलेगा लाभ। आपदा पीड़ित किसानों को ब्याज में 5 फीसदी तक की छूट
- असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना का एलान, 100 रुपये प्रति महीने के अंशदान पर 60 साल की आयु के बाद 3000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी।
- किसान क्रेडिट कार्ड के जरिये कर्ज लेने पर 2 प्रतिशत ब्याज में छूट
- रक्षा बजट पहली बार 3 लाख करोड़ के पार।
- पांच साल में एक लाख डिजिटल गांव।
- फिल्म निर्माताओं के लिए एकल खिड़की को मंजूरी।
- छोटे उद्योगपतियों की भी ली सुध, 1 करोड़ रुपये तक के कर्ज पर 2 फीसदी ब्याज सब्सिडी
- मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए बनेगा अलग विभाग
- घर खरीदने वालों पर जीएसटी का बोझ कम करने की कोशिश, मंत्रीसमूह कर रहा है विचार
- श्रमिकों की न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये तक की गई।
- श्रमिक की मौत पर अब 2.5 लाख रुपये की बजाय 6 लाख रुपये मुआवाजा
- गोवंश के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कामधेनु योजना का ऐलान
- सौभाग्य योजना के तहत सभी घरों को मुफ्त बिजली कनेक्शन, मार्च 2019 तक सभी घरों में बिजली कलेक्शन
- हरियाणा को मिलेगा देश का 22वां एम्स
- रेलवे को 64,587 करोड़ रुपये का आवंटन।
- पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए कर्ज में 2 फीसदी ब्याज छूट की घोषणा
- गौमाता की सेवा के लिए किसानों को 500 रुपये देगी सरकार. एनिमल हसबेंडरी और फिशरी क्षेत्र में 2 फीसदी ब्याज की छूट।
- दूसरे घर से मिलने वाले नोशनल रेंट पर नहीं लगेगा कोई टैक्स
- रियल एस्टेट सेक्टर को राहत, अनसोल्ड इंवेंट्री पर अब दो साल तक मिलेगी टैक्स छूट।
- पोस्ट ऑफिस और बैंक डिपॉजिट पर मिलने वाली आय पर टीडीएस थ्रेसहोल्ड 10,000 रु से बढ़ाकर 40,000 रु की।

## बजट 2019 : शिक्षा क्षेत्र के लिए 93847.64 करोड़ रूपए का आवंटन

**नई दिल्ली :**

सरकार ने अगले वित्त वर्ष के लिए शिक्षा क्षेत्र हेतु 93,847.64 करोड़ रूपए आवंटित किए हैं जो पिछले बजट आवंटन से 10 प्रतिशत से अधिक है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा लोकसभा में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए पेश अंतरिम बजट में उच्च शिक्षा के लिए 37,461.01 करोड़ रूपए तथा स्कूली शिक्षा के लिए 56,386.63 करोड़ रूपए आवंटित किए गये हैं। पिछले वित्त वर्ष में अरूण जेटली ने शिक्षा क्षेत्र के लिए 85,010 करोड़ रूपए आवंटित किए थे। गोयल ने अंतरिम बजट में 2022 तक स्वास्थ्य संस्थानों सहित प्रमुख शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान संबंधी गतिविधियों में निवेश को बढ़ावा देने के मकसद से अगले चार वर्ष के लिए एक लाख करोड़ रूपए आवंटित किए हैं। यह धन शिक्षा में आधारभूत एवं प्रणालियों को 2022 तक फिर से सशक्त करने की योजनाओं के तहत व्यय किये जाएंगे। सरकार ने अनुसंधान एवं अभिनव पहलों के लिए 608.87 करोड़ रूपए आवंटित किए हैं।

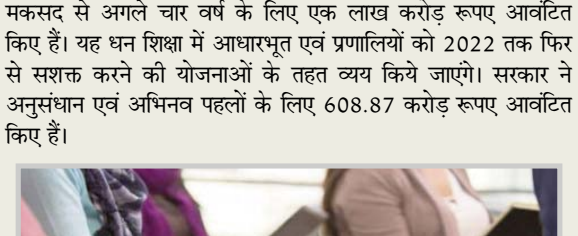

## बजट से नए भारत के निर्माण के लिए नई ऊर्जा मिलेगी : मोदी

**नई दिल्ली :** प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बजट की प्रशंसा करते हुए कहा है कि इससे नये भारत के निर्माण के लिए 130 करोड़ देशवासियों को नयी ऊर्जा मिलेगी। मोदी ने वर्ष 2019-20 के लिए लोकसभा में पेश अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया करते हुए कहा है कि यह सटीक योजनाओं के माध्यम से देश को शक्तिशाली बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। बजट में मीडिल क्लास से लेकर श्रमिकों तक, किसान उन्नति से लेकर कारोबारियों की प्रगति तक, इनकमटैक्स रीलिफ से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक , मैन्यूफैक्चरिंग से लेकर एमएसएमई सेक्टर तक, हाऊसिंग से लेकर 'हेल्थकेयर तक, 'इकोनॉमी को नई गति से लेकर 'न्यू इंडिया के निर्माण तक सबका ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि बजट में 12 करोड़ से ज्यादा किसानों को , 3 करोड़ से ज्यादा मध्यम वर्ग के टैक्स पेयर परिवारों को और 30- 40 करोड़ श्रमिकों को सीधा लाभ मिलना तय हुआ है। सरकार के प्रयासों से गरीबी रिकार्ड गति से कम हो रही है लाखों करोड़ों लोग गरीबी को परास्त करके न्यू मीडिल क्लास क्लास में प्रवेश कर रहे हैं। सरकार की योजनाओं ने देश के हर व्यक्ति के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। आयुष्मान भारत योजना का लाभ 50 करोड़ गरीबों को मिलेगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और सुरक्षा बीमा योजना का लाभ 21 करोड़ गरीबों को मिल रहा है। स्वच्छ भारत मिशन का लाभ 9 करोड़ से ज्यादा परिवारों को हुआ है। उज्ज्वला योजना के तहत छह करोड़ से ज्यादा परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना की वजह से 1.5 करोड़ परिवारों को अपने पक्के घर मिले हैं। उन्होंने कहा कि यह मध्यम वर्ग और उच्चतम मध्यम वर्ग की उदारता, ईमानदारी और प्रतिबद्धता है जिसकी वजह से देश को कर मिलता है और योजनाएं बनती हैं, गरीब का कल्याण होता है। वर्षों से यह मांग रही है कि पांच लाख रूपए तक की आय को कर मुक्त घोषित किया जाए। सरकार ने इस मांग को पूरा किया है।

# पांच लाख

## सालाना आय तक कोई टैक्स नहीं

**नई दिल्ली।**

लोकसभा चुनावों से पहले मोदी सरकार ने नौकरीपेशा लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। अरुण जेटली की जगह बजट पेश कर रहे वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की कि अब पांच लाख रुपये तक सालाना आमदनी वालों को कोई आयकर नहीं देना होगा। पहले यह सीमा 2.50 लाख रुपये थी। इससे लोगों को सालाना 12,500 रुपए तक की बचत हो सकेगी। वित्त मंत्री के यह घोषणा करते ही संसद में मोदी मोदी के नारे गूंज उठे। इसके अलावा, पीयूष गोयल ने घोषणा की कि सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि यदि 6.5 लाख रुपये तक की कमाई करने वाले प्रोविडेंट फंड और अन्य इक्विटीज में निवेश करते हैं तो कोई टैक्स नहीं देना होगा। वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि अब लोग 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर लोग 6.5 लाख रुपये तक कर छूट हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा, अब 40 हजार रुपये तक एफडी पर भी कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा।

## किसानों को दी गई आर्थिक मदद 'खैरात' नहीं बल्कि देश के अन्नदाताओं का सम्मान है: पीयूष गोयल

**नई दिल्ली।** केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट पेश करने के बाद न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि किसानों को दी गई आर्थिक मदद 'खैरात' नहीं बल्कि यह देश के 12 करोड़ अन्नदाताओं का सम्मान है. विपक्ष पर निशाना साधते हुए गोयल ने कहा कि एसी रूम में बैठने वाले नहीं जानते कि 600 रुपये कितने महत्वपूर्ण होते हैं. हालांकि इंटरव्यू के दौरान उन्होंने स्वीकार किया कि किसान मुश्किलों का सामना कर रहे हैं. गोयल ने कहा, 'किसान इस राशि का इस्तेमाल दवाई खरीदने, खाद-बीज खरीदने के लिए कर सकता है. इस तरह की पहले कोई योजना नहीं थी. पीएम मोदी को किसानों को बड़ी चिंता है. पूर्ववर्ती सरकारें ने किसानों और लोगों के स्वास्थ्य की चिंता नहीं की. हमने गांवों की बिजली दी और ग्रामीण भारत के लिए आयुष्मान भारत योजना लॉन्च की.'किसान कर्जमाफी पर उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस ने केवल लंबे वादे किए और चुनिंदा लोगों का कर्ज माफ किया. गोयल ने देश में बेरोजगारी दर 2017-18 में 45 साल के उच्च स्तर 6.1 प्रतिशत पर पहुंच जाने संबंधी रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि मोदी सरकार के पिछले साढ़े चार साल के कार्यकाल में विभिन्न प्रोजेक्ट और आधारभूत संरचनाओं के जरिये रोजगार दिए गए हैं. उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया है और साहसिक कदम उठाए हैं.' जब गोयल से पूछा गया कि एनडीए शासनकाल में भी किसानों के आत्महत्या की कई घटनाएं सामने आई हैं, इस सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों पर काफी ध्यान दिया है. उन्होंने कहा, 'हम किसानों को एक साल में तीन फसल लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं. मोदी सरकार किसानों को शिक्षित करने और उन्हें बेहतर सिंचाई सुविधाएं देने का प्रयास किया है.'

# 2019 का रण जीतने के लिए पीएम मोदी के 6 'सिक्सर', विपक्ष 'क्लीन बोल्ड'

**नई दिल्ली। सरकार ने आम चुनाव से पहले शुक्रवार को पेश अपने आखरी बजट प्रस्तावों में किसानों, मजदूरों और मध्यम वर्ग को लुभाने के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं. चुनावी वर्ष में पीएम मोदी ने सभी वर्गों को खुश करने की कोशिश की है. बजट के जरिये मोदी सरकार ने जो '6 सिक्सर' लगाए हैं, उससे विपक्ष भी भौचक रह गया है. तो आइए एक-एक करके उन सभी छह सिक्सर के बारे में जानते हैं.**

### छोटे किसानों को 6,000 रुपये का नकद समर्थन

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि नाम से एक नई योजना के तहत छोटे किसानों को तीन किस्तों में सालाना 6,000 रुपये की नकद सहायता देने का ऐलान किया. इस योजना से सरकारी खजाने पर सालाना 75,000 करोड़ रुपये का वार्षिक बोझ पड़ेगा. यह सहायता दो हेक्टेयर से कम जोत वाले किसानों को उपलब्ध होगी. वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना से 12 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे. किसानों को सालभर में दो- दो हजार रूपये की तीन किस्तों में कुल 6,000 रुपये उनके खाते में हस्तांतरित किए जाएंगे. इसे दिसंबर 2018 से लागू किया गया है. सरकार का कहना है कि जल्द ही पहली किश्त किसानों के खाते में डाली जाएगी. इसे मोदी सरकार का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है.

### मजदूरों के लिए मेगा पेंशन योजना

अंतरिम बजट में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री ''श्रम योगी मानधन योजना'' की घोषणा की गई है. इसके तहत श्रमिकों को 60 साल की आयु के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी. योजना के तहत श्रमिकों को मासिक 100 रुपये का योगदान करना होगा. इसके साथ ही 100 रुपये की राशि सरकार की तरफ से भी दी जायेगी. इससे 10 करोड़ श्रमिकों को फायदा होगा. इसे दूसरा सबड़े बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है. इस योजना में कोई भी मजदूर 29 साल की उम्र तक शामिल हो सकता है और उसे 100 रुपये प्रति माह जमा कराने होंगे, जबकि जो मजदूर इसमें 18 साल की उम्र में शामिल होंगे, उसे 55 रुपये प्रति माह जमा कराने होंगे।

### नौकरी-पेशा को छूट

मोदी सरकार ने ने मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा तबके की मांग को स्वीकार करते हुये पांच लाख रुपये तक की व्यक्तिगत आय को टैक्स फ्री कर दिया है. वित्त मंत्री गोयल ने कहा कि पांच लाख रुपये तक की आमदनी वालों को अब कर देने की जरूरत नहीं होगी. ऐसे लोग जिनकी सालाना आय 6.5 लाख रुपये तक है और उन्होंने जीवन बीमा, पांच साल की सावधि जमा तथा अन्य कर बचत वाली योजनाओं में निवेश किया है तो उन्हें भी अपनी पूरी आय पर छूट मिल सकती है. सरकार के इस कदसे से तीन करोड़ मध्यम वर्ग करदाताओं, स्वरोजगार करने वालों और वरिष्ठ नागरिकों को कुल मिलाकर 18,500 करोड़ रुपये तक का लाभ मिलेगा. चिकित्सा बीमा और पेंशन योजना में निवेश करने वालों को मिलाकर लाभार्थियों की संख्या और बढ़ जाएगी. इसके अलावा, सरकार ने ग्रेज्युटी की सीमा बढ़ाकर 20 लाख कर दी है. इसके अलावा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआई) नियम के तहत पात्रता 15,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपये प्रतिमाह वेतन की गई.

### गांव और गाय पर फोकस

इसके अलावा, सरकार ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए आबंटन बढ़ाकर 750 करोड़ रुपये कर दिया. इससे गाय संसाधनों का सतत अनुवांशिक उन्नयन करने और गायों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी. यह आयोग गायों के लिए कानूनों और कल्याण योजना को प्रभावी रूप से लागू करने की भी देखभाल करेगा. इसके अलावा मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास के बारे में सतत ध्यान केंद्रित करने के लिए सरकार ने अलग से मत्स्य पालन विभाग का सृजन करने का निर्णय किया है. कृषि क्षेत्र में संकट से निपटने के लिए गोयल ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों के लिए भी दो प्रतिशत की ब्याज सहायता की घोषणा की, जबकि समय पर ऋण भुगतान के लिए उन्हें भी तीन प्रतिशत अधिक सहायता की पेशकश की गई है. 1 लाख डिजिटल गांव बनाने की बात बजट में की गई है.

### जवानों का बढ़ा जोश

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को घोषणा की कि 2019-20 में रक्षा बजट तीन लाख करोड़ रुपये से ज्यादा कर दिया गया है और पहली बार यह इस आंकड़े को पार कर रहा है. वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) के लिए सरकार पहले से ही 35,000 करोड़ रूपये से अधिक आवंटित कर चुकी है. सरकार सभी सेनाकर्मियों की सैन्य सेवा वेतनमान (एमएसपी) में महत्वपूर्ण रूप से बढ़ोतरी और अत्यधिक जोखिम से भरे क्षेत्रों में तैनात नौसेना और वायुसेना कर्मियों को विशेष भत्ते दिये जाने की घोषणा कर चुकी है.

### आयुष्मान भारत योजना

केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने 2019-2020 के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 61,398 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान की घोषणा की जिसमें 6400 करोड़ रुपये केंद्र की महत्वाकांक्षी आयुष्मान योजना के लिए आवंटित किये गए हैं. आने वाले वित्त वर्ष के लिए स्वास्थ्य आवंटन पिछले दो वित्त वर्ष में सर्वाधिक है. केंद्र की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के लिए 6400 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर को इसकी शुरुआत की थी. योजना में हर साल देश में 10 करोड़ से अधिक परिवारों को लाभ पहुंचाने का उद्देश्य है और इसमें सालाना पांच लाख रुपये तक के अस्पताल के इलाज खर्च के बीमा का प्रावधान है. आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक 10 लाख लोगों का इलाज हुआ है. यह दुनिया की सबसे बड़ी चिकित्सा लाभ योजना है.

## संपादकीय

संयुक्त राष्ट्र का यह आकलन कि इस वर्ष और अगले वर्ष भारत की आर्थिक विकास दर दुनिया में सबसे तेज रहेगी यह न सिर्फ भारत के लिए राहतकारी है बल्कि मोदी सरकार के आर्थिक सुधारों की कामयाबी पर मुहर भी है। मोदी सरकार आर्थिक सुधारों व लोकहितकारी निर्णयों की कसौटी पर खरा उतरी है, जिससे देश में निवेश और आर्थिक गतिशीलता का प्रतिस्पर्धात्मक माहौल बना है। सरकार इसी तरह अपना काम करती रहे।

# आर्थिक विकास व सुधारों पर मुहर

**संयुक्त** राष्ट्र का यह आकलन कि इस वर्ष और अगले वर्ष भारत की आर्थिक विकास दर दुनिया में सबसे तेज रहेगी यह न सिर्फ भारत के लिए राहतकारी है बल्कि मोदी सरकार के आर्थिक सुधारों की कामयाबी पर मुहर भी है। यूएन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स (डब्ल्यूईएसपी) के अनुसार, अगले वित्त वर्ष 2019-20 में भारत की विकास दर बढ़कर 7.6 फीसद होने की संभावना है। रिपोर्ट के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में भी रफ्तार 7.4 फीसद रह सकती है। इन आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है कि विकास दर के मामले में भारत चीन से काफी आगे रहेगा। ध्यान दें तो मौजूदा वर्ष 2019 में चीन की विकास दर 6.3 फीसद रह सकती है जबकि पिछले साल 6.6 फीसद रही थी। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक 2020 में चीन की रफ्तार और घटकर 6.2 फीसद रह सकती है। गौर करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर गत वर्ष अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भी मोदी सरकार की आर्थिक सुधारवादी नीतियों पर मुहर लगाई। अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 13 वर्ष बाद भारत की रेटिंग को बीएए-3 से बढ़ाकर बीएए-2 कर दिया जो रेखांकित करता है कि आर्थिक सुधारों की गति सही दिशा में है।

यह जानना आवश्यक है कि बीएए-3 रेटिंग का आकलन निवेश की संभावनाएं क्षीण और कमजोर अर्थव्यवस्था से लगाया जाता है जबकि बीएए-2 का संकेत निवेश संभावनाएं अधिक होने के साथ अर्थव्यवस्था की गति तेज होने से संबंधित है। ध्यान देना होगा कि अपने कार्यकाल के प्रारंभ से ही मोदी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में चालू खाते का घाटा कम करना, विकास दर को ऊंचे पायदान पर ले जाना, बचत में वृद्धि, निवेश चक्र बनाए रखना मुख्य एजेंडा में शामिल रहा है। ऐसे में अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर यूएन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स (डब्ल्यूईएसपी) और मूडीज के रुख में परिवर्तन आया है तो यह स्वाभाविक ही है। ध्यान देना होगा कि यूपीए-2 की सरकार के अंतिम दिनों में अमेरिकी निवेशकों द्वारा कहा गया था कि वे भारतीय बाजार में उतरने को सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। दरअसल उनका इशारा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार और यूपीए सरकार की नीतिगत अक्षमता की ओर था। तब अमेरिकी बैंक जेपी मॉर्गन ने भारत की ऋण साख को घटाकर स्थिर श्रेणी में डाल दिया था। दूसरी ओर वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने मनमोहन सरकार की आर्थिक नीतियों की जमकर आलोचना की थी।

सरकार की आर्थिक नीतियों से परेशान होकर पोस्को और आर्सेलर मित्तल जैसी कई कंपनियों के अलावा आस्ट्रेलिया की पेट्रोलियम कंपनी बीएचपी बिलिटॉन ने भारत से अपना कारोबार समेटने का निर्णय किया। तब के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और वित्तमंत्री पी चिदंबरम बैंकरों और देशी-विदेशी कारोबारियों को लगातार आश्वासन दे रहे थे कि सरकार अटकी पड़ी परियोजनाओं को चालू करके अर्थव्यवस्था को गति देगी पर इन दोनों अर्थशास्त्रियों का भरोसा रसातल में समाती अर्थव्यवस्था को थामने में मददगार साबित नहीं हुआ। विडंबना है कि इसके बावजूद भी मनमोहन सिंह और पी चिदंबरम मोदी सरकार की अर्थनीति को कठघरे में खड़ा कर रहे हैं, जबकि दुनिया की हर वैश्विक आर्थिक संस्थाएं मोदी सरकार की अर्थनीति की तारीफ कर रही हैं। याद होगा चंद महीने पहले डेलाएट इंडिया ने अपने ताजा सर्वेक्षण में कहा कि भारत आने वाले कुछ दशक में आर्थिक सुपर पॉवर बनेगा और उसका आधार मोदी सरकार का आर्थिक सुधार कार्यक्रम है, लेकिन मजे की बात यह है कि विपक्षी दल अब भी नोटबंदी, सरकारी योजनाओं में आधार कार्ड का उपयोग, दिवाला कानून और जीएसटी जैसे सुधारवादी नीति की आलोचना कर रहे हैं।

ऐसा नहीं है कि विपक्ष को नोटबंदी और काले धन के खिलाफ सरकार के उपायों से होने वाले फायदे की जानकारी नहीं है। उन्हें पता है कि नोटबंदी के जरिए सरकार ने ऐसे छह हजार मुखौटा कंपनियों को चिह्नित करने में सफल हुई जिन्होंने नोटबंदी के दौरान बैंक खातों का इस्तेमाल काले धन को सफेद करने के लिए किया। विपक्ष इससे भी अंजान नहीं है कि नोटबंदी के बाद सरकार ने दो लाख से अधिक मुखौटा कंपनियों के खातों के बारे में बैंकों से छानबीन करने को कहा था और बैंकों ने अपने छानबीन में ऐसे 5820 कंपनियों के 13 हजार 140 खातों की पड़ताल की जिसमें नोटबंदी के दौरान करोड़ों रुपए जमा हुए और खाते सीज होने से पहले निकाल लिए गए। लेकिन ऐसे लोग सीबीआइ और प्रवर्तन निदेशालय के राडार पर हैं। भारत सरकार के प्रयास के कारण ही स्विट्जरलैंड अपने यहां जमा काले धन की जानकारी देने को तैयार है। विपक्ष सरकार की इन उपलब्धियों से भले ही अपनी आंख बंद कर ले लेकिन अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं आंखें खुली रखे हैं।

मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने एसबीआइ एवं एचडीएफसी बैंक समेत सार्वजनिक क्षेत्र की ओएनजीसी, आइओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल और एनटीपीसी समेत नौ कंपनियों की दीर्घकालीन रेटिंग में इजाफा किया है जो दर्शाता है कि दुनिया भारत को उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। मूडीज के निर्णय से जहां विदेशी पूंजी प्रवाह सहित निवेश में तेजी आएगी वहीं विदेशी कर्ज की लागत कम होगा। शेयर व बांड्स बाजार में विदेशी निवेशकों की रुचि बढ़ेगी। इससे भारतीय कंपनियों को फंड जुटाने में भी मदद मिलेगी। बुनियादी क्षेत्र के विकास के लिए पैसा जुटाना आसान होगा। प्रोजेक्टों को गति देने में मदद मिलेगी और कर्ज को निचले स्तर पर रखने में काफी सहूलियत होगी। विदेशी कंपनियों की नजर में भारतीय अर्थव्यवस्था की साख बढ़ेगी। यह स्थिति आगे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी साबित होगी। अब विपक्ष चाहे जो भी आलोचना करे लेकिन यूएन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स और मूडीज का मूल्यांकन सरकार के अच्छे राजकाज, पारदर्शी निर्णय और निवेश नीति की अनुकूलता को ही अभिव्यक्त करता है। यूएन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज की रिपोर्ट पर सवाल उठाने वाले आर्थिक विशेषज्ञों को समझना होगा कि जिन मुद्दों पर वे सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना कर रहे हैं उन मसलों पर वैश्विक संस्थाएं भारत सरकार की नीतियों की तारीफ कर रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर में तेजी और रेटिंग में सुधार एक किस्म से देश की तस्वीर में हुए बदलावों पर मुहर है और साथ ही यह भी रेखांकित करने वाला है कि मोदी सरकार अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रही है। केंद्र सरकार की नीतिगत सक्रियता का परिणाम है कि विश्व के निवेशकों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर विश्वास बढ़ रहा है।

केंद्र सरकार भी भारत में कारोबारी माहौल निर्मित करने और भारत को एक ग्लोबल मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में नियमों और कानूनों में व्याप्त कमियों को दूर कर रही है। पिछले दिनों ही सरकार ने जीएसटी के दरों में बदलाव किया है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी अपनी विदेशी यात्राओं में विदेशी निवेशकों को भारत की परियोजनाओं में निवेश करने के लिए उत्साहित कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि उसका सकारात्मक असर देखने को भी मिल रहा है। केंद्र सरकार की नीतिगत सक्रियता का परिणाम है कि चालू खाते का घाटा कम हुआ है और विकास दर ऊंचे पायदान की ओर अग्रसर है। बचत में वृद्धि हुई है और मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र में उत्पादन बढ़ा है। सरकार आपूर्ति पर जोर देकर महंगाई को काबू करने में काफी हद तक सफल हुई है। निवेश बढ़ने से ढांचागत क्षेत्रों का विस्तार हो रहा है। ऐसे में कहना अतिश्योक्तिपूर्ण नहीं कि मोदी सरकार आर्थिक सुधारों व लोकहितकारी निर्णयों की कसौटी पर खरा उतरी है, जिससे देश में निवेश व आर्थिक गतिशीलता का प्रतिस्पर्धात्मक माहौल बना है।

**अरविंद जयतिलक**
(वरिष्ठ पत्रकार)

## विचार

# बजटः सरकार के सामने कई चुनौती

चुनाव के मद्देनजर वित्त मंत्री इस बार अंतरिम बजट में कोई बड़ा ऐलान जरूर करेंगे। हालांकि, यह ऐलान ऐसा नहीं होंगे कि इसे सीधे तौर पर वोट बैंक को खुश करने के तौर पर देखा जाए, मोदी सरकार यही चाहेगी कि होने वाली घोषणाएं आर्थिक सुधार के रूप में हों।

मोदी सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट शुक्रवार को पेश होगा। आम चुनाव 2019 से पहले पेश होने वाले अंतरिम बजट पर पूरे देश की नजर है। परंपरा के तौर पर आम चुनाव से पहले पेश होने वाले बजट में बड़े ऐलान नहीं किए जाते हैं। इसमें नई सरकार के आने तक खर्च चलाने जितनी रकम के लिए संसद की मंजूरी ली जाती है। हालांकि, अगले 3-4 महीने में आम चुनाव होने हैं। ऐसे में लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस बार परंपरा तोड़ कर मोदी सरकार लोक-लुभावन बजट पेश करेगी। मगर जानकारों के मुताबिक, चुनाव के मद्देनजर वित्त मंत्री इस बार अंतरिम बजट में कोई बड़ा ऐलान जरूर करेंगे। हालांकि, ये ऐलान ऐसा नहीं होंगे कि इसे सीधे तौर पर वोट बैंक को खुश करने के तौर पर देखा जाए, मोदी सरकार यही चाहेगी कि अंतरिम बजट में होने वाले घोषणाएं आर्थिक सुधार के रूप में हो। वित्त मंत्री डायरेक्ट टैक्स रिपोर्ट (प्रत्यक्ष कर रिपोर्ट) भी पेश करेंगे। अतः माना जा रहा है कि अंतरिम बजट में टैक्स स्लैब में भी बदलाव किए जा सकते हैं।

इसके अलावा, पेंशनरों और किसानों को लेकर भी कुछ बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं। एक उम्मीद यह भी है कि होम लोन को लेकर सरकार कुछ रियायत का ऐलान करे। मिडिल क्लास या नौकरी पेशा वर्ग को भी मोदी सरकार के इस आखिरी बजट से काफी उम्मीदें होंगी। विपक्ष ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को लगातार घेरा है। संभव है कि सरकार युवाओं को लुभाने के लिए बजट में किसी ठोस नीति का ऐलान करे। ऐसा न करके सरकार वोट बैंक खोना नहीं चाहेगी और युवाओं को खुश करने का सरकार के पास चुनाव से पहले यही आखिरी मौका होगा। इस बजट में सरकार से यह उम्मीद तो कतई नहीं की जाती है कि वो कोई ऐसा ऐलान कर दे, जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति पर बहुत बड़ा असर पड़े क्योंकि, अगर ऐसा होता है, तो इसका असर चुनाव में दिखेगा। इस साल लोकसभा चुनाव के साथ कम से कम पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इनमें आंध्र प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा और जम्मू-कश्मीर चुनावों के लिहाज से अहम हैं। हाल के चुनाव नतीजों को देखें, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा सरकार को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है।

किसान वर्ग मौजूदा सरकार से खासा नाराज है और जाहिर सी बात है कि अगर अंतरिम बजट में भी सरकार ने उनकी अनदेखी कि तो आम चुनाव में किसानों की नाराजगी साफ दिखेगी। आम चुनाव से पहले किसानों और युवाओं की नाराजगी दूर करने के लिए मोदी सरकार के पास यूनिवर्सल बेसिक इनकम के रूप में एक विकल्प है. लेकिन, इसे इतने कम वक्त में और इतने बड़े स्तर पर कैसे लागू किया जाए, इस पर बहुत रिसर्च की जरूरत होगी। अगर ये स्कीम लागू हो जाती है, तो ये मौजूदा वितरण प्रणाली की जगह लेगी। ऐसे में सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी कि वह चुनाव के मद्देनजर अपने अंतरिम बजट में सभी वर्गों को कैसे खुश कर पाती है?

# स्वाइन फ्लू बन रहा है चुनौती

**साल**-2014 में पोलियो मुक्त होने के बाद अब भारत बर्ड फ्लू जैसी भयंकर बीमारी से भी मुक्त हो गया है। बर्ड फ्लू का अंतिम मामला नौ मई-2016 को कर्नाटक के हुमनाबाद में सामने आया था, जिसके बाद वहां के पक्षियों को मारकर सफाई का काम हुआ। उसके बाद देश के किसी भी कोने से बर्ड फ्लू की शिकायत नहीं आई है। दो गंभीर बीमारियों पर काबू पाना निःसंदेह हमारे लिए गर्व की बात है। मगर स्वाइन फ्लू का बढ़ता दायरा अब हमें चिंतित करता जा रहा है। यह एक ऐसी बीमारी है, जो एक समय तक गंदी बस्तियों या कस्बों या काफी हद तक छोटे शहरों तक ही सिमटी थी, लेकिन हाल के वर्षों में यह बीमारी महानगरों तक पहुंच बना चुकी है। अब तो आलीशान बंगले और सुरक्षा में घिरे सरकारी आवासों की दीवारों को यह बीमारी पार कर चुकी है। स्वाइन फ्लू की बीमारी हर साल लोगों को चौंकाती रही है।

अब यह बीमारी स्वरूप बदल चुकी है। वर्षाकाल के दौरान सिर्फ इसके व्यापक होने की खबरें आ जाती हैं। डॉक्टरों ने भी रिपोर्ट में कई बार इस बीमारी के व्यापक होने की आशंका जाहिर की है। बहरहाल, स्वाइन फ्लू ने सारे देश में दहशत मचा रखी है। अचानक यह महामारी सुरसा की तरह फैली और देखते ही देखते महानगरों को अपनी चपेट में ले लिया। आमतौर पर तो पशुओं और पालतू जानवरों को होने वाले वायरस के हमले कभी इंसानों तक नहीं पहुंचते। इसकी वजह यह है कि जीव विज्ञान की दृष्टि से इंसानों और जानवरों की बनावट में फर्क है। अभी तक देखा यह गया था कि जो लोग सूअर पालन के व्यवसाय में हैं और लंबे समय तक सूअरों के संपर्क में रहते हैं, उन्हें ही स्वाइन फ्लू होने का जोखिम अधिक रहता है। मध्य 20वीं सदी से अब तक के चिकित्सा इतिहास में केवल 50 केस ही ऐसे हैं, जिनमें वायरस सूअरों से इंसानों तक पहुंचा हो।

स्वाइन फ्लू के लक्षण सामान्य एन्फ्लूएंजा के लक्षणों की तरह ही होते हैं। बुखार, तेज ठंड लगना, गला खराब हो जाना, मांसपेशियों में दर्द होना, तेज सिरदर्द होना, खांसी आना और कमजोरी महसूस करना आदि लक्षण इस बीमारी के दौरान उभरते हैं। इस साल जो स्वाइन फ्लू का संक्रमण हुआ है, वह तीन अलग-अलग तरह के वायरसों के सम्मिश्रण से उपजा है। फिलहाल इस वायरस के उद्गम अज्ञात हैं। वर्ल्ड ऑर्गनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यह वायरस अब केवल सूअरों तक सीमित नहीं है, इसने इंसानों के बीच फैलने की ताकत हासिल कर ली है। अमेरिका में साल-2005 से अब तक केवल 12 मामले ही सामने आए हैं। एन्फ्लूएंजा वायरस की खासियत यह है कि यह अपना स्वरूप बदलता रहता है। इसकी वजह से यह उन एंटीबॉडीज को भी छका देता है, जो पहली बार हुए एन्फ्लूएंजा के दौरान विकसित हुई थीं। यही वजह है कि एन्फ्लूएंजा के वैक्सीन का इस वायरस पर असर नहीं होता। वर्ष 1930 में पहली बार एच1एन1 वायरस के सामने आने के बाद से 1998 तक इस वायरस के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 1998 और 2002 के बीच इस वायरस के तीन विभिन्न स्वरूप सामने आए थे। इनके भी पांच अलग-अलग जीनोटाइप थे। मानव जाति के लिए जो सबसे बड़ा जोखिम सामने है, वह है स्वाइन एन्फ्लूएंजा वायरस के म्यूटेट करने का, जो कि स्पेनिश फ्लू की तरह घातक भी हो सकता है। चूंकि, यह इंसानों के बीच फैलता है इसलिए सारे विश्व के इसकी चपेट में आने का खतरा है।

हालांकि, भारत में इस बीमारी से प्रभावित लोगों की संख्या बहुत कम है, लेकिन दहशत का एक बड़ा कारण है कि इस बीमारी के प्रभावित होने पर जांच के लिए देश में प्रयोगशालाओं की संख्या पर्याप्त नहीं है और दवाओं का भंडारण कम है। वर्तमान में मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हाई रिस्क वाले जोन में रखे गए हैं। वर्ष-2009, 2010, 2012, 2013 व 2015 में बीमारी से ग्रस्त होने वालों की संख्या सबसे ज्यादा रही है। सरकार के सामने मुश्किल यह है कि एक ओर उसे जहां बीमारी से प्रभावित लोगों का सफलतापूर्वक इलाज करना है, तो वहीं बीमारी से लोगों में फैली दहशत पर भी काबू पाना है। हालांकि, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बहुत पहले ही चेता दिया था कि यह बीमारी दुनिया में महामारी के रूप में फैल सकती है, लेकिन देश में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत को देखते हुए स्वाइन फ्लू की बीमारी ने जनता में महामारी से कहीं ज्यादा खौफनाक होने का डर घर कर लिया है।

उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाकों में भी अगर स्वाइन फ्लू का प्रकोप बढ़ रहा है, तो यह समझने की जरूरत है कि इसे कोई मौसमी रोग मान कर अनदेखी करने का नतीजा क्या हो सकता है। इस बुखार ने जिस तरह अपने पांव फैलाए हैं, उससे साफ है कि इससे बचाव के एहतियाती इंतजामों को लेकर देश भर में संबंधित सरकारी महकमे कितने लापरवाह रहे हैं। खबरों के मुताबिक जनवरी के पहले तीन हफ्तों में ही देश भर में स्वाइन फ्लू के करीब दो हजार 800 मामले सामने आ चुके हैं और 85 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले राजस्थान में मरीजों की तादाद लगभग साढ़े बारह सौ है और अब तक 50 लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं, दिल्ली के अलग-अलग अस्पतालों से 532 लोगों के इसकी चपेट में होने की खबर है। जबकि पिछले पूरे साल सिर्फ 218 लोगों को स्वाइन फ्लू होने की खबर आई थी।

सामान्य जुकाम या बुखार एवं इसके लक्षणों के बीच बड़ा फासला नहीं है, इसलिए अक्सर इसकी चपेट में आए लोगों को इसे पहचानने में देरी हो जाती है। जबकि अगर शुरुआत से ही इसे लेकर सावधानी बरती जाए, वक्त पर इसकी पहचान करके जरूरी इलाज कराया जाए तो इसके जानलेवा होने की आशंका कम होती है। मुश्किल यह भी है कि किसी रोग से पैदा समस्या जब तक बेलगाम नहीं हो जाती है तब तक महकमों की नींद नहीं खुलती है।

देश में स्वाइन फ्लू की बीमारी चुनौती बनकर खड़ी है। यह समय बेहद सतर्कता का है। सावधानी और शरीर के प्रति उचित देखभाल ही बेहतर उपाय है। फिर मौसम या किसी अन्य वजह से बीमारी का प्रकोप कम होने लगता है तो सरकार यह सोच कर निश्चिंत हो जाती है कि अब समस्या खत्म हो गई। जबकि जरूरत इस बात की है कि समय रहते इससे बचाव के पूर्व इंतजाम किए जाएं और जागरूकता का संचार किया जाए।

**डॉ. सोनालिका कश्यप**
(स्वतंत्र टिप्पणीकार)

पुण्यतिथि पर विशेष

# सत्यनारायण : पत्रकारिता व साहित्य के बेमिसाल इंसान

**सत्यनारायण** श्रीवास्तव सत्तू भैया पत्रकारिता, साहित्य, कला के साथ समाज की जीवनधाराओं के प्रति जागरूक रहे। निर्भीक पत्रकार के नाते उन्होंने बेबाक एवं ओजस्वी कलम द्वारा उदय, प्रहरी, जागरूक-जनमत सहित प्रमुख दैनिकों के पत्रकार के रूप में खुद को समर्पित कर दिया था। सत्तू भैया राजनीतिक चिंतक भी थे। जबलपुर के प्रहरी से वर्ष 1952 से शुरू हुआ उनका पत्रकारिता का सिलसिला जीवन के अंतिम दौर तक नवभारत में वर्ष 1981 तक चला। बहुत कम लोगों को पता है कि 1980 में मुख्यमंत्री पद को लेकर चली उठा-पटक में सत्यनारायण श्रीवास्तव की भूमिका थी। तब अर्जुन सिंह, शिवभानु सोलंकी, छिंदवाड़ा सांसद कमलनाथ का नाम भी मुख्यमंत्री की दौड़ में था। हालांकि अर्जुन सिंह सफल रहे थे।

सत्तू भैया के कई हस्तियों से प्रगाढ़ संबंध थे। उनमें डॉ. शंकरदयाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह, अर्जुन सिंह, भगवत राव मंडलोई, राजमाता विजयाराजे सिंधिया, नरसिंहराव दीक्षित, पंडित शंभूनाथ शुक्ल, चंद्रप्रताप तिवारी, जगदीश जोशी, ठाकुर निरंजन सिंह, मूलचंद देशलहरा, बाबू तख्तमल जैन, एचवी कामथ आदि हैं। जो राजनेता मुसीबत में सत्तू भैया को बुलाकर कठिन दौर से निकलने के गुर पूछा करते थे, उनमें गोविंद नारायण सिंह, द्वारिका प्रसाद मिश्र, श्यामाचरण शुक्ल, मूलचंद देशलहरा, प्रकाशचंद्र सेठी, अर्जुन सिंह, सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी प्रमुख हैं।

जब वे पहली बार मुझसे रीवा के एक प्रेस में मिले, तो उनका पहला प्रश्न था, तुम कहां के रहने वाले हो। जब मैंने बताया इलाहाबाद, तो उन्होंने छोटे भाई की तरह गले से लगा लिया और बताया कि मेरे पिता स्व. रूपनारायण श्रीवास्तव भी इलाहाबाद के थे। देश व प्रदेश के साहित्यकारों से उतने ही नजदीकी रिश्ते थे, जितने राजनेताओं से। ऐसे साहित्यकारों में दुष्यंत कुमार, शेरी भोपाली, हरिशंकर परसाई, रामेश्वर गुरु, अंचल, बालकवि बैरागी, आगा सुल्तान हैदर, हैदरी, शरद जोशी प्रमुख हैं। 28 अप्रैल, 1928 को नरसिंहपुर में जन्मे सत्यनारायण श्रीवास्तव ने 1948 में पं भवानी प्रसाद तिवारी के पत्र प्रहरी से की थी। वह समय सत्तू भैया के खोजी फनकार होने का एक बेहतरीन चमकता पृष्ठ है। उन्होंने भोपाल से जागरूक-जनमत और नरसिंहपुर से उदय का संपादन भी किया। एक बार मेरे शासकीय आवास 1/17, साउथ टीटी नगर में महफिल जमी थी। महफिल में जो लोग थे, उनमें दुष्यंत कुमार, मैं तथा सत्तू भैया थे। वे दोनों दौरानें गुफ्तगू खुद्दारी पर चर्चा कर रहे थे। मैंने भी खुद्दारी पर शेर सुनाया था, जो वे अक्सर दोहराया करते थे, शेर था-

**यही कांटे तो कुछ खुद्दार हैं सहने गुलिस्तां में।**
**जो शबनम के लिये दामन को फैलाया नहीं करते॥**

जब भी सत्तू भैया का स्मरण होता है, तो मन में एका-एक हूंक सी उठती है, काश आज का पत्रकार सत्यनारायण श्रीवास्तव जैसा होता। यदि ऐसा होता, तो आज पत्रकार जगत की सूरत कुछ और ही होती। चिंतन से भरा उनका जीवन था। एक दिन शरद जोशी और दुष्यंत कुमार बैठे थे। चर्चाओं के दौरान सत्तू भैया ने कहा था- राजकृपा प्राप्त करने वाला पत्रकार कितना भी चाहे, पत्रकारिता की मर्यादा की रक्षा नहीं कर सकता। इसके लिए संपूर्ण पत्रकारिता को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा। वे लेखनी की समर्थता के कारण किंग मेकर तथा किचन कैबिनेट के सरगना भी कहलाए। मगर उनके लेखन की प्रतिबद्धता हमेशा अपने पाठकों के प्रति ही रही। कभी भी वे किसी राजनेता या राजनैतिक दल के पिछलग्गू नहीं कहलाये।

पत्रकारिता के कई आयामों में एक खोजी पत्रकारिता में सत्तू भैया का विशेष योगदान रहा। समर्पण भाव से अंतिम सांस तक कार्य करते हुए पत्रकारिता समुदाय से अलग-थलग रहकर राजनीतिज्ञों में ऊंचे तक की पैठ रखते थे। यहां तक वह कांग्रेस की राजनीति में अंदर तक पैठ रखते थे, जिसने उनके राजनीतिक जीवन के एक जीवंत और गंभीर अध्याय को जोड़ा हुआ था। सूझ-बूझ वाली खोजी पत्रकारिता उनके खून में रची-बसी थी। राजनीतिक रिपोर्टिंग की सत्तू भैया की विशिष्ट शैली से महाकौशल और बाद में रीवा, इंदौर, ग्वालियर तथा भोपाल का हर प्रबुद्ध नागरिक प्रभावित था। आदमी को मृत्योपरांत इन्हीं गुणों की खातिर याद किया जाता है।

**शिवप्रसाद मुफलिस**

## सार समाचार

### म्यामार की जेल में कैद रॉयटर के रिपोर्टरों ने सुप्रीम कोर्ट में की अपील

यांगून। रोहिंग्या संकट की रिपोर्टिंग करने से जुड़े आरोपों को लेकर म्यामां में सात साल की कैद की सजा का सामना कर रहे समाचार एजेंसी रॉयटर के दो पत्रकारों के वकीलों ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। कानूनी प्रक्रिया के जरिए राहत पाने का यह उनके लिए आखिरी मौका है। म्यामां के नागरिक एवं रिपोर्टर वा लोन (32) और क्याव सो ओ (28) को दिसंबर 2017 में यांगून में गिरफ्तार किया गया था। सरकारी गोपनीयता कानून का उल्लंघन करने को लेकर बाद में उन्हें जेल भेज दिया गया था। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने कहा है कि रोहिंग्या लोगों के नरसंहार की उनकी रिपोर्टिंग को दबाने के लिए उनके रिपोर्टरों पर ये आरोप लगाए गए। गौरतलब है कि जनवरी में यांगून के हाई कोर्ट ने उनकी शुरूआती अपील खारिज कर दी थी, जिसके बाद उनके पास कानूनी प्रक्रिया के तहत सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प बचा था।

### फ्रांस में 2018 में बलात्कार की शिकायतें तेजी से बढ़ी: गृह मंत्रालय

पेरिस। फ्रांस में 2018 में बलात्कार तथा यौन अपराधों से जुड़ी शिकायतों में तेजी से वृद्धि हुई है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों में इस बात का खुलासा हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक, बलात्कार की शिकायतें 17 फीसदी वहीं यौन अपराध से जुड़ी शिकायतें 20 फीसदी तक बढ़ गई हैं। मंत्रालय की सांख्यिकी सेवा की एक रिपोर्ट के अनुसार, ''ये आंकड़े हार्वे वाइंस्टाइन के हाथों महिलाओं के उत्पीड़न...और उसके बाद शुरू हुए मीटू अभियान की पृष्ठभूमि में फैली जागरुकता के बीच सामने आए हैं।'' रिपोर्ट के अनुसार,'' पीड़ितों की बड़ी संख्या इसलिए भी सामने आई है क्योंकि ऐसे मामलों की शिकायतें ज्यादा हुई हैं और इस प्रकार की हिंसा को बर्दाश्त नहीं करने की प्रवृत्ति बढ़ी है।''

### सोमालिया में अमेरिकी हवाई हमलों में 24 आतंकवादी ढेर

वाशिंगटन। अमेरिकी सेना ने सोमालिया में हवाई हमले किए जिसमें अल-शबाब के 24 आतंकवादी मारे गए। अमेरिका अफ्रीका कमान ने गुरुवार को एक बयान में बताया कि मध्य सोमालिया के हिरान क्षेत्र में ''आतंकवादियों के ठिकाने'' के समीप एक दिन पहले हमला किया गया। यह कार्रवाई उस अभियान के तहत की गई जिसमें अमेरिकी सेनाएं शबाब जिहादी आंदोलन का मुकाबला करने के लिए अफ्रीकी संघ और सोमाली राष्ट्रीय सुरक्षा बलों के साथ काम कर रही हैं। अफ्रीका कमान के अभियान निदेशक मेजर जनरल ग्रेग ओल्सन ने कहा, ''ऐसे हमले सोमालिया और क्षेत्र में शांति का विरोध करने वाले विदेशी आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई में हमारे साझेदारों को प्रगति करने में मदद करते रहेंगे।'' पेंटागन ने हाल के वर्षों में सोमालिया में हमले तेज कर दिए हैं क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन बाधाओं को कम कर दिया है कि कब अमेरिकी सेना कथित आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है।

### 12 सालों से नाक में फंसी सोने की अंगूठी छींक से आई बाहर

वाशिंगटन। अमेरिका में एक शीर्ष भारतीय-अमेरिकी संगठन ने हाई स्कूल के भारतवंशी छात्रों को उनकी मातृभूमि से जोड़ने के लिये पूरी तरह से वित्तपोषित छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू करने का ऐलान किया है। तीन सप्ताह के इस कार्यक्रम के तहत छात्रों को भारत का दौरा कराया जाएगा। इंडियास्पोरा ने इस कार्यक्रम को 'हेरिटिज इंडिया' नाम दिया है। कार्यक्रम का संचालन 360प्लस द्वारा किया जा रहा है। दोनों संगठन लाभ निरपेक्ष हैं। बुधवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि भारत और उसकी प्रवासी आबादी के बीच रिश्ता बनाना और उसे बढ़ावा देना इस कार्यक्रम का लक्ष्य है।

# अमेरिका: भूख हड़ताल पर बैठे भारतीयों पर ढ़हाया गया जुल्म, नाक में नली डालकर जबरन खिलाया गया खाना

**वॉशिंगटन (एजेंसी)।**

अमेरिका में आव्रजन अधिकारियों ने भूख हड़ताल पर बैठे कई भारतीयों समेत कम से कम छह अप्रवासी बंदियों को नाक में नली डालकर जबरदस्ती खाना खिलाया है. टेक्सास में एक केंद्र के हालातों के विरोध में इन बंदियों ने भूख हड़ताल की थी. भारतीय-अमेरिकी समूहों ने इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया है. अधिकारियों ने बताया कि आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) ने एक बयान में कहा है कि बुधवार की रात एल पासो में 11 बंदियों ने खाना खाने से मना कर दिया था और देशभर में विभिन्न आईसीई नजरबंदी केन्द्रों पर चार अन्य लोग भी भूख हड़ताल पर चले गये थे.

आईसीई ने बताया कि एल पासो में भूख हड़ताल कर रहे 11 में से छह लोगों को जनवरी के मध्य में एक संघीय न्यायाधीश के आदेशों के तहत जबरदस्ती खाना खिलाया गया. जिन लोगों को भोजन खिलाया गया है वे लगभग दो सप्ताह से भूख हड़ताल पर थे. अधिकारियों ने बताया कि 11 लोगों में से दो लोगों ने बुधवार को अपनी भूख हड़ताल शुरू की.

टेक्सास में दो बंदियों की वकील रूबी कौर ने कहा कि उनके मुवक्किल भारतीय अप्रवासी है जो लगभग छह महीने पहले दक्षिणी सीमा से अमेरिका में आये थे. कौर ने बताया, ''उन्हें नाक में नली डालकर तरल पदार्थ दिये गये है. यह बेहद ही दर्दनाक है और उनकी इच्छा के खिलाफ है.'' आईसीई की प्रवक्ता ने इन आरोपों पर सीधी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है.

अमेरिका में भारतीय-अमेरिकी समुदाय ने उन रिपोर्टों पर चिंता जाहिर की है जिनमें कहा गया है कि संघीय आव्रजन अधिकारी भारतीय बंदियों को जबरदस्ती खिला रहे है. उत्तरी अमेरिकी पंजाबी एसोसिएशन (एनएपीए) ने एक बयान में कहा कि टेक्सास में एल पासो केंद्र में 11 भारतीय बंदियों ने खाने से मना कर दिया था. एनएपीए के कार्यकारी निदेशक सतनाम सिंह चहल ने कहा, ''किसी भी अप्रवासी को जबरदस्ती खाना खिलाना मानवाधिकारों का उल्लंघन है.'' उन्होंने कहा कि इनमें से कुछ बंदी 30 से अधिक दिनों से भूख हड़ताल पर थे.

# शिखर वार्ता: ट्रंप अगले हफ्ते बताएंगे किम जोंग-उन से बातचीत करने की तिथि और स्थान

**वाशिंगटन।** अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि वह फरवरी के अंत में उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के साथ होने वाली दूसरी शिखर वार्ता की तारीख और जगह का ऐलान अगले सप्ताह करेंगे। ट्रंप ने कहा कि वह मंगलवार को कांग्रेस में अपने स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन के दौरान कार्यक्रम का ऐलान करना चाहते हैं। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक ट्रंप ने पत्रकारों को बताया कि वे बैठक करना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन ने उत्तर कोरिया की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रित करने के संबंध में आश्चर्यजनक प्रगति की है। ट्रंप ने कहा कि जनवरी 2017 में मेरे कार्यभार संभालने से पहले ऐसा लगता था कि हम उत्तर कोरिया के साथ युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब उत्तर कोरिया न तो मिसाइल, न रॉकेट और न ही परमाणु परीक्षण कर रहा है।

# सीरिया में मारी गई पत्रकार के परिवार को अमेरिका देगा 30.2 करोड़ डॉलर का मुआवजा

**वाशिंगटन। (एजेंसी)।**

वॉशिंगटन के एक न्यायाधीश ने द संडे टाइम्स की लंबे समय तक विदेशी संवाददाता रही पत्रकार मैरी कोल्विन की 2012 में हुई मौत को लेकर सीरियाई सरकार से उनके परिवार को 30.2 करोड़ डॉलर देने के लिए कहा है. अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट अदालत के न्यायाधीश एमी बर्मन जैक्सन ने बुधवार देर रात को दिए फैसले में कहा कि सीरियाई सेना ने होम्स शहर में उस अस्थायी मीडिया केंद्र को जानबूझकर निशाना बनाया जहां कोल्विन और अन्य पत्रकार काम कर रहे थे.

केंद्र पर लगातार हमलों के चलते 22 फरवरी 2012 को कोल्विन और फ्रांसीसी पत्रकार रेमी ओचलिक की मौत हो गई थी. ब्रिटिश समाचार पत्र के लिए दुनिया भर में संघर्षों को कवर करने वाली कोल्विन की पहचान बायी आंख पर बांधी जाने वाली काली पट्टी थी. उन्हें 2001 में श्रीलंका में एक ग्रेनेड हमले के कारण एक आंख से दिखना बंद हो गया था. साल 2018 में आई फिल्म ''ए प्राइवेट वार'' उनकी जिंदगी पर आधारित थी.

कोल्विन के परिवार के वकीलों ने दलील दी कि यह मौत कोई दुर्घटना नहीं थी. उन्हें विदेशों में सीरियाई सरकार की संपत्तियों को कुर्क करके 30.2 करोड़ डॉलर की धनराशि बरामद करने की उम्मीद है. सीरियाई सरकार ने कभी इस मुकदमे का जवाब नहीं दिया. कोल्विन के परिवार के प्रमुख वकील स्कॉट गिलमोर ने कहा, ''अब चुनौती इस फैसले को लागू करना है.''

# आसिया बीबी स्वतंत्र नागरिक है उन्हें कहीं भी जाने की आजादी हैं: पाक विदेश मंत्रालय

**इस्लामाबाद (एजेंसी)।**

पाकिस्तान ने गुरूवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में ईश निंदा के मामले में बरी की गई ईसाई महिला आसिया बीबी स्वतंत्र नागरिक है और उन्हें देश के भीतर या बाहर कहीं भी यात्रा करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश आसिफ सईद खोसा की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ ने 47 वर्षीय आसिया बीबी को बरी करने के न्यायालय के फैसले पर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता डाक्टर मोहम्मद फैसल ने साप्ताहिक प्रेस कांफ्रेंस में कहा ,'' वह आजाद नागरिक है। वह पाकिस्तान में रहना चाहती है तो यहां रह सकती हैं। यदि बाहर जाना चाहती है तो जा सकती है। यह उनकी इच्छा है और इस पर कोई पाबंदी नहीं है।''

वह सुरक्षात्मक निगरानी में है और सरकार ने उनके ठिकाने के बारे में बताने से इनकार कर दिया। फैसल ने कहा,''मेरी जानकारी में आसिया बीबी अभी भी पाकिस्तान में है।'' चार बच्चों की मां आसिया जल्दी ही पाकिस्तान छोड़ सकती है क्योंकि यहां उनकी जान को खतरा है । उनकी दो बेटियां पहले ही कनाडा बस चुकी हैं। उन्हें 2009 में पंजाब प्रांत के ननकाना साहिब इलाके में एक खेत में काम करते समय एक मुस्लिम महिला से झगड़े के दौरान कथित तौर पर अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल के कारण गिरफ्तार किया गया था । मुस्लिम महिला की शिकायत पर स्थानीय धार्मिक नेता ने शिकायत दर्ज कराई थी।

आसिया को 2010 में सुनवाई अदालत ने दोषी करार दिया और लाहौर उच्च न्यायालय ने 2014 में उसे दी गई मौत की सजा बरकरार रखी । उच्चतम न्यायालय ने हालांकि पिछले साल फैसला बदल दिया जिसके बाद कई दिनों तक इस्लामी कट्टरपंथी दलों ने हिंसक विरोध प्रदर्शन किया।

# नेपाल में प्रधानमंत्री कार्यालय के निकट छात्रों ने काले झंडे लगे गुब्बारे उड़ाए

**काठमांडू (एजेंसी)।**

नेपाल में छात्रों के एक समूह ने प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली के सिंहदरबार स्थित कार्यालय के निकट गुब्बारे उड़ाए जिस पर काले झंडे लगे हुए थे। चिकित्सा क्षेत्र में सुधार और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार द्वारा कार्रवाई नहीं करने के खिलाफ छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।

नेपाल की विपक्षी पार्टी 'नेपाली कांग्रेस' के छात्र संगठन नेपाल स्टूडेंट्स यूनियन के सदस्य यहां प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने काले झंडे और बैनर लगे गुब्बारे उड़ाए। बैनरों पर ''आंदोलनरत चिकित्सक गोविंदा के सी की जान बचाने'', 13 वर्षीय एक लड़की से बलात्कार और हत्या के मामले के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और भ्रष्टाचार खत्म करने जैसे नारे लिखे हुए थे।

एनएसयू के केंद्रीय सदस्य सुशील भट्टा ने कहा कि काले झंडे उड़ाने के पीछे का मकसद सरकार पर अपनी मांगों की पूर्ति के लिए दबाव बनाना है। इस बीच, आपातकालीन सेवा के अलावा सभी अस्पताल बंद रहे। चिकित्सकों एवं दंत चिकित्सकों के संगठन नेपाल मेडिकल एसोसिएशन ने पिछले 23 दिन से अनशन पर बैठे डॉक्टर के सी के समर्थन में हड़ताल का आह्वान किया है। वह चिकित्सा क्षेत्र में सुधार की मांग को लेकर अनशन पर हैं।

# अमेरिका की सैन्य अकादमियों में यौन उत्पीड़न के मामले बढ़े: रिपोर्ट

**वाशिंगटन (एजेंसी)।**

अमेरिका की सैन्य अकादमियों में बीते दो साल में कड़े कदम उठाने के बावजूद यौन उत्पीड़न के मामले करीब 50 फीसदी तक बढ़े हैं। बृहस्पतिवार को जारी पेंटागन की एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। करीब 12,900 कैडेट सेना, नौसेना और वायुसेना अकादमियों में शामिल होते हैं जहां उन्हें अमेरिका के भावी अधिकारियों के तौर पर प्रशिक्षित किया जाता है। हर दूसरे साल, इन कैडेट से अनचाहे यौन संपर्क अथवा यौन उत्पीड़न से जुड़े एक गुमनाम सर्वे को भरने को कहा जाता है। 2018 के आंकड़ों के मुताबिक 747 लोगों ने किसी न किसी प्रकार के यौन उत्पीड़न की बात कही है। वहीं 2016 में 507 लोगों ने यही बात कही थी। इस तरह दो साल में यौन उत्पीड़न के मामलों में करीब 47 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि हुई है। पेंटागन के कार्मिक एवं तत्परता विभाग की प्रमुख एलिस वेन विंकले ने कहा कि ये नतीजे कुंठित करने वाले, निराशाजनक और अस्वीकार्य हैं। यौन उत्पीड़न के मामले सबसे ज्यादा न्यूयॉर्क स्थित सेना की वेस्ट प्वाइंट अकादमी में सामने आए जहां 16.5 प्रतिशत महिलाओं ने यौन उत्पीड़न की बात कही। इससे पहले यह आंकड़ा 10.2 प्रतिशत था। अमेरिकी सेना के शीर्ष अधिकारियों ने एक बयान में कहा कि ये आंकड़े परेशान और निराश करने वाले हैं। पेंटागन ने कहा कि अतीत में यौन उत्पीड़न के मामलों को बड़े पैमाने पर जागरुकता अभियान चलाकर रोक दिया गया था जिसके बेहतर नतीजे सामने आए थे। लेकिन इस साल यह समस्या और विकराल हो गई है।

# वेनेजुएला के विपक्षी नेता का आरोप, मादुरो के एजेंटों ने उनके परिवार को धमकाया

**काराकास (एजेंसी)।**

वेनेजुएला के विपक्ष के नेता जुआन गुएडो ने कहा है कि एलीट सुरक्षा बल उनके परिवार को धमकी देने के लिए उनके घर में घुसे। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से बेदखल करने की उनकी कोशिश को मिल रहे अंतरराष्ट्रीय समर्थन के बीच गुएडो ने मादुरो सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। इस कदम से नेशनल असेंबली के 35 वर्षीय नेता की सुरक्षा को लेकर डर बढ़ गया है। गुएडो ने पिछले सप्ताह मादुरो सरकार को सीधी चुनौती देते हुए अपने आप को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित किया था। गुएडो ने काराकास विश्वविद्यालय में अपने भाषण में कहा कि पुलिस का विशेष कार्रवाई बल एफएईएस उनकी पत्नी फैबिएना रोसेल्स से पूछताछ करने के लिए उनके घर गया था।

उन्होंने कहा, ''एफएईएस मेरे पत्नी फैबिएना से पूछताछ करने के लिए मेरे घर आए। इस समय तानाशाही का मानना है कि वह हमें डरा धमका देंगे।'' मंच पर पत्नी के साथ मौजूद गुएडो ने कहा कि उनकी 20 माह की बेटी घर पर है और ''मेरी बच्ची के साथ जो भी होगा'' उसके लिए एफएईएस जिम्मेदार है। उन्होंने कहा, ''मेरा उद्देश्य स्पष्ट है। मैंने इन अधिकारियों को कहा कि सीमा पार मत करो।'' इन घटनाक्रमों के बीच अमेरिका ने मादुरो को चेतावनी दी है कि अगर वह विपक्षियों को निशाना बनाते हैं तो उन्हें ''गंभीर परिणाम'' भुगतने होंगे।

लातिन अमेरिकी देश में बढ़ते असंतोष पर मादुरो ने कार्रवाई करते हुए हाल के वर्षों में कई विपक्षी नेताओं को जेल भेजा। इससे पहले बृहस्पतिवार को यूरोपीय सांसदों ने गुएडो को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में मान्यता दे दी जो समाजवादी नेता को सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर करने के वास्ते उनकी कोशिश में एक अन्य कदम है। बढ़ते अंतरराष्ट्रीय समर्थन के बीच गुएडो तेल सम्पन्न देश में मादुरो के खिलाफ सड़कों पर दबाव बना रहे हैं। उन्होंने शनिवार को जन आंदोलन का आह्वान किया है।

उधर वेनेजुएला की शीर्ष अदालत ने गुएडो की संपत्ति फ्रीज कर दी है और उन्हें देश ना छोड़ने के लिए कहा है। यूरोप के चार अहम देशों ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन ने कहा कि अगर मादुरो सप्ताहांत तक नए सिरे से राष्ट्रपति चुनाव नहीं कराते तो वे भी गुएडो को अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में मान्यता दे देंगे। अमेरिका ने गुरुवार को सभी यूरोपीय देशों से गुएडो को मान्यता देने का अनुरोध किया था। इस बीच, अमेरिका ने गुरुवार को मादुरो से गुएडो द्वारा दिए क्षमादान की पेशकश स्वीकार करने का अनुरोध किया। ।

अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने ट्वीट किया, ''मैं चाहता हूं कि

निकोलस मादुरो और उनके शीर्ष सलाहकार सेवानिवृत्ति लेकर वेनेजुएला से कहीं दूर किसी सुंदर समुद्र तट पर रहे। उन्हें राष्ट्रपति गुएडो की माफी का फायदा उठाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जितना जल्दी हो, उतना अच्छा।'' गौरतलब है कि गुएडो ने पेशकश दी कि जिसने भी राष्ट्रपति को अस्वीकार किया उन्हें क्षमादान दिया जाएगा और उन्होंने मादुरो के लिए भी ऐसी ही पेशकश दी। मादुरो ने कहा कि वह विपक्ष के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं लेकिन उन्होंने ताजा राष्ट्रपति चुनाव कराने के विचार को खारिज कर दिया।

# संक्षिप्त कामकाजी यात्रा पर भारत आयेंगे बेंजामिन नेतन्याहू

**नयी दिल्ली (एजेंसी)।**

विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि ईजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू संक्षिप्त कामकाजी यात्रा पर भारत आयेंगे जिसका कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि यह यात्रा महज चंद घंटों की होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ''हम इस्राइल के प्रधानमंत्री का उनकी संक्षिप्त भारत यात्रा पर स्वागत करने के लिए राजी हैं। इस यात्रा की तारीख और अन्य ब्यौरे अभी तैयार ही किये जा रहे हैं।'' सऊदी अरब के शहजादे मोहम्मद बिन सलमान की भारत यात्रा की योजना संबंधी खबर पर उन्होंने कहा, ''हम इस यात्रा के कार्यक्रम को तैयार करने की कोशिश में अब भी लगे हुए हैं। जब तारीख तय हो जाएंगी, आपको जानकारी दे दी जाएगी।'' फरार अरबपति मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण के भारत के अनुरोध पर एक सवाल के जवाब में कुमार ने कहा कि उसके प्रत्यर्पण के लिए अपनी कोशिश हम जारी रखेंगे। उसके प्रत्यर्पण का मुद्दा एंटीगुआ और बारबुडा सरकार के समक्ष विचाराधीन है। चोकसी पर अपने भांजे नीरव मोदी के साथ कथित साठगांठ से सरकारी पंजाब नेशनल बैंक को चूना लगाने का आरोप है।

## वीर नर्मद द.गु. युनिवर्सिटी में तीन दिवसीय

# मेगा प्लेसमेंन्ट मेले का उद्घघाटन आरोग्य मंत्री किशोर भाई कनानाणी ने किया

सूरत। राज्य के यवाओं को मेले के माध्यम से रोजगार दिलाने के लिए द.गु. युनिवर्सिटी कन्वेशन हाल में आरोग्य राज्य मंत्री किशोर कानाणी के हाथो तीन दिवसीय प्लेसमेन्ट मेले का शुभारंभ हुआ।

इस प्रोग्राम में किशोरभाई कानाणी ने बताया की राज्य सराकर द्वारा अग्रणी कंपनीओं और विविध विद्यालयों में पिछले वर्ष में पढने वाले विद्यार्थियों के बीच में कड़ी बनाने के लिए इस मैगा प्लेसमेन्ट कैम्प का आयोजन गुजरात में प्रथम बार किया जा रहा है। राज्य में विविध कंपनीओं में कुल 70000 पद खाली है। कनाणी ने बताया की ये खाली पदों पर सिर्फ 50000 विद्यार्थियों को नौकरी मिली है। कानाणी ने कहा कि यवाओं को स्मार्ट फोन की तरह स्मार्ट बनने की सिख लेना चाहिए, राज्य सरकार द्वारा कोलेजों में पढने वाले युवाओं में विविध प्रकार की स्किल विकसित करने के लिए फिनिर्शींग स्कुल की शुरुआत करी है। जिसमें 40-40 विद्यार्थियों के बैच में विविध प्रकार की ट्रेनिंग देने की पहल करी है। युवाओं को रोजगार प्राप्त हो सके इसके लिए विद्यार्थियों को सही तरीके से इन्ट्रव्यु दे सके और योग्य जगह नौकरी प्राप्त करे इसके लिए के.सी.जी. अहमदाबाद की तरफ से हरेक कोलेजों में अध्यापक दिए है ताकी वो योग्य तालीम दे सके।

सूरत। उधना जोन के दबाण विभाग में उठाकर लाए गए समान को चोरी से बेचने की शिकायत करने पर अलग-अलग अधिकारियों के अलग-अलग जवाब दे रहे है। जगदीश पटेल अ. कमिश्नर- लोगों के फरियाद से तंग आ गए है इसी लिए वे लोगों से कह रहे है कि इसकी एफआईआर पुलिस स्टेशन में जाकर दर्ज करवाओं। वी. के परमार डे. इंजनेर- में मेरी 25 साल की नौकरी में इतना अधिकारी का दबाव में कार्य करना पड़ता है। हमे उपर से अधिकारियों द्वारा निर्देश दिया जाता है कि रोड़ किनारे लगे लारी गल्लों को उठा कर लाओं। दबाण विभाग जो समान लोगों के उठा कर लाते है उसकी रिकार्ड में जानकारी नहीं होती, ज्यादातर माल सामान अधिकारी कर्मचारी, बेच डालते है ? इस तरह की फरियाद काफी समय से लोगों द्वारा दी जा रही और ऐसे अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग की जा रही है। लेकिन लारी गल्ला वालों के पास अपने सामान की कोई रशीद या पक्के में कोई परुफ न होने के कारण इन फरियादों पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

### केंद्र के बजट के साथ गुजरात सरकार की घोषणा

# ४८७ करोड़ रुपये के खर्च से १० नए फ्लायओवर बनेंगे

**नये फ्लायओवर तीन हिस्सों में बनेंगे जिसमें फ्लायओवर उत्तर, मध्य गुजरात, सौराष्ट्र के मुख्य रास्तों पर बनेंगे**

अहमदाबाद । लोकसभा के आगामी चुनाव को ध्यान में रखकर केन्द्र की मोदी सरकार का बजट शुक्रवार को पेश हुआ है तब दूसरी तरफ, गुजरात सरकार ने भी कई बड़ी घोषणा की है। राज्य सरकार ने यहां ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान लाने के लिए राज्य के तीन हिस्सों में दस नए फ्लायओवर बनाने की घोषणा की है । यह सभी फ्लायओवर पहले चरण में है और करीब ४८७ करोड़ रुपये के खर्च से तैयार किया जाएगा। गुजरात में यह नये फ्लायओवर यह तीन हिस्सों में बनेंगे जिसमें सभी दस फ्लायओवर उत्तर, मध्य गुजरात और सौराष्ट्र के मुख्य रास्तों पर बनाये जाएंगे। राज्य के उपमुख्यमंत्री नीतिन पटेल द्वारा इस मामले में महत्वपूर्ण घोषणा की गई थी कि, करीब ४८७ करोड़ रुपये से ज्यादा के खर्च से राज्य में दस नए फ्लायओवर बनेंगे, जिसकी वजह से ट्राफिक की समस्या आसान होगी। इसके साथ ही लोगों को विशेष करके वाहनचालकों को आवागमन और ट्रांसपोर्टेशन में काफी आसानी होगी। उन्होंने आगे बताया कि, सड़क निर्माण विभाग ने राज्य के ढांचे को फैलाने के लिए आयोजन किया है। आयोजन के पहले चरण में नये फ्लायओवर के लिए करोड़ों रुपये की व्यवस्था की गई है।

### कहां बनेंगे नए फ्लायओवर और कितना खर्च होगा.....

अहमदाबाद। (१) आणंद करमसद हाईवे पर बोरसद में -४५ करोड़ रुपये के खर्च से
(२) सिद्धपुर के देथली कोर्स रोड पर -३५ करोड़ रुपये के खर्च से
(३) पाटण के नवजीवन होटल क्रॉस रोड पर -२७ करोड़ रुपये के खर्च से
(४) भूज-लखपत रोड पर (दो फ्लायओवर) -३६ करोड़ रुपये के खर्च से
(५) मेहसाणा के मोढेरा क्रॉस रोड पर -११० करोड़ रुपये के खर्च से
(६) सूरत कडोदरा रोड पर -११० करोड़ रुपये के खर्च से
(७) सौराष्ट्र राजकोट जामनगर रोड पर -६० करोड़ रुपये के खर्च से
(८) गांधीनगर में रक्षा शक्ति सर्कल पर -५० करोड़ रुपये के खर्च से
(९) गांधीधाम टकोर रोड पर -१७ करोड़ रुपये के खर्च से

# पश्चिम रेलवे के मेगा ब्लोक की वजह से छह ट्रेनें रद्द हुई

अहमदाबाद । शनिवार को पश्चिम रेलवे के लोअर परेल स्टेशन पर ११ घंटे के मेगा ब्लोक की वजह से सौराष्ट्र और अहमदाबाद को मुंबई से जोड़ने वाली कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी । यह मेगा ब्लोक की वजह से शनिवार को दुरंतो सहित की छह महत्व की ट्रेनें रद्द की गई है । जिसकी वजह से अहमदाबाद -मुंबई के बीच यात्रियों का शनिवार का शीड्यूल ठप होने की संभावना है ।

पश्चिम रेलवे के लोअर परेल स्टेशन पर शनिवार को रात के १० बजे से दूसरे दिन सुबह के ९ बजे तक ११ घंटे का मेगा ब्लोक स्टेशन के कामकाज के लिए लिया गया है, जिसकी वजह से शनिवार को राज कोट से चलने वाली और आती दोनों राजकोट-मुंबई सेंट्रल दुरंतो रद्द किया गया है। अहमदाबाद से मुंबई आती और जाती सभी ट्रेन शनिवार को दो से तीन घंटे लेट होने की संभावना है। मेगा ब्लोक की वजह से इंदोर -मुंबई दुरंतो, मुंबई -वलसाड पैसेन्जर, गुजरात क्वीन सहित की ट्रेन भी रद्द किए जाने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, इसके साथ शनिवार को ओखा से रवाना होती ट्रेन नंबर २२९४६ ओखा-मुंबई सेन्ट्रल सौराष्ट्र मेल को बोरिवली स्टेशन पर रोक दिया जाएगा । इसी वजह से ट्रेन बोरिवली-मुंबई सेंट्रल के बीच रद्द रहेंगी । इसके अलावा ३ फरवरी को मुंबई सेंट्रल से रवाना होती ट्रेन नंबर १९०१५ मुंबई सेंट्रल -पोरबंदर सौराष्ट्र एक्सप्रेस मुंबई सेंट्रल से अपने निर्धारित समय से लेट रवाना होगी । उत्तर -पश्चिम रेलवे के अजमेर डीविजन में पालनपुर-आबूरोड की मावल -जेटी स्टेशन के बीच डबलिंग कामकाज चल रहे होने के कारण राजकोट डीविजन की दो ट्रेन के रूट डाइवर्ट किए गए हैं, जिसमें १ फरवरी की ओखा से रवाना होती ट्रेन नंबर १९५६५ ओखा-देहरादून उत्तरांचल एक्सप्रेस मेहसाणा, पालनपुर, आबू रोड, अजमेर, जयपुर, दिल्ली सराई रोहिल्ला के बदले में वाया अहमदाबाद, वडोदरा, रतलाम, भरतपुर होकर डायवर्ट की गई । जबकि शुक्रवार को ट्रेन नंबर १९५८० दिल्ली सराई रोहिल्ला-राजकोट एक्सप्रेस वाया अजमेर, गोधरा, आणंद, अहमदाबाद होकर गई थी ।

### पूजारी के विरूद्ध गुजरात में भी ११ अपराध दर्ज

# इनपुट की वजह से डॉन रवि पूजारी की गिरफ्तारी संभव

**गुजरात एटीएस ने जानकारी दी कि, डॉन रवि पूजारी अफ्रीका में छिपा हुआ है, जिससे सेनेगल से गिरफ्तार किया गया**

अहमदाबाद। अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पूजारी की दक्षिण अफ्रीका के सेनेगल से गिरफ्तार किए जाने से गुजरात सहित देशभर में सनसनी मच गई । हालांकि, सबसे उल्लेखनीय बात है कि, डॉन रवि पूजारी की गिरफ्तारी गुजरात एटीएस के इनपुट की वजह से संभव हुई है । गुजरात एटीएस ने ही केंद्रीय जांच एजेंसियों को जानकारी दी गई थी कि, डॉन रवि पूजारी अफ्रीका में छिपा हुआ है, जिसकी वजह से सेनेगल में इसे गिरफ्तार किया गया । डॉन रवि पूजारी ने अहमदाबाद सहित गुज रात के बिल्डरों तथा राजनेताओं के पास फिरौती मांगकर खलबली मचा दी। इसके अलावा बॉलिवुड इंडस्ट्री के लोगों को डराने का काम भी वह करता था । गुज रात एटीएस के महत्वपूर्ण इनपुट की वजह से ही डॉन रवि पूजारी गत दिन अफ्रीका के सेनेगल से गिरफ्तार किया गया । डॉन रवि पूजारी के विरूद्ध अहमदाबाद सहित राज्यभर में इसके विरूद्ध

में फिरौती, धमकी सहित के ११ अपराध दर्ज किए गए हैं, जिसकी जांच आगामी दिनों में खुलने की संभावना रही है । उल्लेखनीय है कि, डॉन रवि पूजारी ने गत वर्ष वडगाम के विधायक जिग्नेश मेवाणी की हत्या करने की धमकी दी थी, तब अमूल कंपनी के एमडी आरएस. सोढी के पास २५ करोड़ रुपये की फिरौती मांगी थी। जिसकी जांच क्राइमब्रांच फिलहाल कर रही है । राज्य के पूर्व मंत्री जयंतीभाई कवाडिया के पास दो दिन फोन पर रवि पूजारी गैंग के शख्सों ने पांच लाख रुपये देने की फिरौती मांगी थी । इसी प्रकार से पालडी क्षेत्र में स्थित उमा सोसाइटी में रहते बिल्डर परेश पटेल से भी पांच करोड़ रुपये की फिरौती मांगी थी । डॉन रवि पूजारी ने अक्सर गुज रात और मुंबई के उद्योगपति तथा फिल्मी इंडस्ट्री के साथ जुड़े लोगों के पास से करोड़ों रुपये की फिरौती मांगी थी । आगामी दिनों में रवि पूजारी को देश में लाया जाएगा तो गुजरात पुलिस इसे गिरफ्तार करके पूछताछ करेगी। रवि पूजारी सेनेगल के डकार क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित, **संपादक :- सुरेश मौर्या** फोन नं. (9879141480) **RNI.No. : GUJHIN/2018/75100, E-mail: krantisamay@gmail.com ( subject to surat jurisdiction)**